मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

कैदी की पीठ पर 'ॐ' लिखा 3
चुनावी बान्ड्स पर मोदी को झटका 4
साजिश के पीछे है बड़ा हाथ : गोगोई 5
जलियांवाला संघर्ष अभी ज़ारी है 6
वंशवाद के विरोध में मंत्री वीरेन्द्र सिंह! 8

वर्ष 32 अंक -23 फ़रीदाबाद 21-27 अप्रैल 2019 फोन - 9999595632 2.50 ₹

फरीदाबाद शहर में मंत्री कृष्णपाल व विधायक सीमा को दिखाया गया आइना

फ़रीदाबाद (म.मो.) स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर दोबारा सांसद बनने को लालायित हैं। भाजपा का टिकट मिल चुका है, इसकी खुशी में रात भर जश्न मना कर पास-पड़ोस के लोग़ों की नींद हराम कर दी थी। अब जनता को दोबारा ठगने के लिये कृष्णपाल जनता के बीच सभायें करते घूम रहे हैं। देहाती क्षेत्रों में अपनी हाय-हाय कराने के बाद बीते सोमवार को उन्होंने बड़खल विधायक सीमा त्रिखा व पार्षद जसवंत सिंह के सहयोग से 5 नम्बर मार्केट में बांके बिहारी मंदिर के निकट निरंकारी चौक पर नुक्कड़ सभा करने का प्रयास किया।

शहर के व्यस्ततम इलाकों में से एक इस चौक पर शाम के वक्त आने-जाने वालों का तांता लगा रहता है, परन्तु क्षेत्र के पार्षद, विधायक व सांसद की ओर देखने व उन्हें सुनने के लिये किसी के पास फुर्सत नहीं थी। लिहाजा नुक्कड़ सभा फ्लॉप हो गयी और जनता को बहकाने व ठगने आये नेतागण अपना सा मुंह लेकर चलते बने। इन नेताओं के प्रति जनता का यह व्यवहार उन्हें आइना दिखाने के लिये काफ़ी समझा जा रहा है। जो नेता मुख्यमंत्री खट्टर की बगल में वाहनों पर खड़े होकर जनता के बीच से अपनी शाही सवारी निकाल कर प्रसन्न थे, उन्हें जनता ने अपनी औकात बतानी शुरू कर दी है।

राज्य सरकार के स्तर पर सीमा त्रिखा व केन्द्र सरकार के स्तर पर मंत्री गूजर का शहरियों के प्रति क्या योगदान है जो वे उनकी सभाओं में आकर जुटें व उनकी जिंदाबाद करें? विधायक बनने से पूर्व बड़खल झील को लबालब भरने वाली सीमा को आज सूखी झील मुंह चिढा रही है। सरकारी बीके अस्पताल में न पर्याप्त डॉक्टर व अन्य स्टाफ़ हैं, न दवायें व उपकरण आदि हैं। आये दिन गर्भवती महिलायें स्वास्थ्य केन्द्रों पर भटकती हुई कभी पेड़ के नीचे तो कभी अस्पताल के दरवाजे पर बच्चा जन रही हैं। तमाम सरकार स्कूलों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। प्राइवेट स्कूलों की महंगी शिक्षा ग़रीबों की पहुंच से बाहर है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। शराब तस्करी व जुआ-सट्टा खुलेआम चलता है बल्कि इन धंधों को चलाने वाले अगल-बगल रहते हैं।

केन्द्र सरकार के स्तर पर पांच साल में गूजर जी से मंझावली पुल नहीं बना जबकि बीते पांच साल में आये दिन गूजर जी पुल बनने के लाभ गिनाते व उसकी झूठी प्रगति रिपोर्ट जनता को परोसते रहे। शहर के बीचो-बीच बन रहा राष्ट्रीय राजमार्ग आज भी अधूरा है और इसके त्रुटिपूर्ण डिजायन के चलते इस पर लगातार जानलेवा दुर्घटनायें हो रही हैं। मजे की बात यह है कि इस राजमार्ग के निर्माण हेतु जनता से हर रोज़ डेढ करोड़ रुपये टोल टैक्स के जरिये वसूला जा रहा है और मंत्री गूजर ने इसके उद्घाटनों पर बीसियों नारियल फ़ोड़ डाले हैं।

केन्द्र सरकार के रेल विभाग ने यहां के यात्रियों के लिये पांच साल में मात्र एक फुटओवर ब्रिज, एक प्लेटफ़ार्म से दूसरे पर जाने का शिलान्यास किया है। जो चौथी लाइन पांच साल पहले तक बन चुकी थी आज भी वहीं तक है। ओल्ड रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग पांच साल से ज्यों की त्यों अधूरी खड़ी है। यात्रियों को ट्रेनों में भूसे की तरह लद कर जाना पड़ता है। केन्द्र सरकार का इएसआई निगम हरियाणा भर के 30 लाख मज़दूरों से करीब 3500 करोड़ सालाना तो वसूल लेता है लेकिन चिकित्सा व अन्य सेवायें देने के लिये वह एक हज़ार करोड़ भी खर्च नहीं करता जिससे मज़दूरों का परेशान होना स्वाभाविक है।

हां, सत्तारूढ होकर उन नेताओं ने अपनी जायदादें व काली कमाई खूब बढाई है। यह रहस्य जनता से छिपा नहीं है। यह जनता है सब जानती है, कृष्णपल जी को जनता से ज्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सारे प्रदेश में अपनी ईमानदारी का ढोल बजाते घूम रहे हैं। माना कि उनसे पहले के हुड्डा और चौटाला शासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला था; लेकिन अगर खट्टर ने भ्रष्टाचार का अन्त कर दिया तो वे बतायें कि कितने भ्रष्ट मंत्री, विधायक, अफसर और पार्टी दलाल उनके राज में जेलों में भेजे गये ?

खट्टर ने पंजाबी समुदाय को वोट बैंक में बदला

हरियाणा के चुनावी इतिहास में आप पहली बार पंजाबी समुदाय को किसी राजनीतिक पार्टी के बंधुआ वोट बैंक में बदलते देख रहे हैं। खट्टर शासन ने इस आर्थिक और शैक्षिक रूप से आगे निकले हुए शहरी समुदाय में घोर असुरक्षा की भावना भर कर उन्हें भाजपा के लिए वोट बैंक में बदलने का काम अंजाम दिया है।

अमूमन एक कमजोर समुदाय ही असुरक्षा या लालच के चलते वोट बैंक बनता है। कभी कांग्रेस इस खेल में माहिर होती थी। मसलन, उसने राज्य के मेवात अंचल के मेव समुदाय को अशिक्षित और पिछड़ा रख कर उनका वोट बैंक के रूप में दोहन किया। भजन लाल के दौर में उसने जाटों का हौव्वा खड़ा कर गैर-जाट वोटर को वोट बैंक तो नहीं लेकिन एक वोट अपील की तर्ज पर जरूर भुनाया। 2019 के इस चुनाव में खट्टर शासन की नाकामियां ही उसके काम आ रही हैं।

जाट आरक्षण आन्दोलन के दौर में हरियाणा के शहरों ने कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ते देखी थीं। पूरे एक हफ्ते खट्टर की पुलिस सभी को राम भरोसे छोड़कर नदारद हो गयी थी। जियो-मरो, लुटो-पिटो, प्रशासन कहीं नजर नहीं आता था। कायदे से तो लोगों को खट्टर से इस कुशासन का हिसाब मांगना चाहिये था, लेकिन देखने को मिल रहा है कि लोग इस कदर डरा दिए गए हैं कि वे पंजाबी की सुरक्षा के नाम पर पंजाबी वोट बैंक बनने जा रहे हैं।

हालाँकि महज एक समुदाय के वोट बैंक बन जाने से चुनाव नहीं जीता सकता। पर खट्टर के पास इस दांव के आलावा और कोई चारा भी नहीं। न प्रदेश में कोई विकास के बताने योग्य काम हुए हैं, न हरियाणा में हिन्दू-मुस्लिम कार्ड खेलने का बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। इसलिए पंजाबी समुदाय को वोट बैंक बना कर और दूसरों को बाँट कर ही भाजपा द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा।

नामांकन का पहला दिन: प्रशासनिक व्यवस्था अस्त व्यस्त

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 16 अप्रैल को नामांकन का पहला दिन था। सारी प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था कन्फ्यूज़्ड थी। किसी को कुछ पता नहीं था कि उसे क्या करना है। सबसे पहला तमाशा तो सुरक्षा के नाम पर तैनात पुलिसिया भीड़ के रूप में देखने को मिला। इंकलाबी मज़दूर केन्द्र के साथी संजय मौर्य नामांकन हेतु जुलूस लेकर गाते-बजाते डीसी कार्यालय की ओर चले। उनका यह जुलूस राजमार्ग की ओर से सेक्टर 11-12 की विभाजक सड़क पर चल रहा था। ज्योंहीं यह जुलूस डीसी कार्यालय की ओर मुड़ने लगा तो पुलिस की भीड़ ने उन्हें 20 गज़ अगले मोड़ से मुड़ने को कह कर आगे की ओर बढा दिया। वहां मौजूद पुलिस भीड़ ने भी उनको आगे की ओर धकेल दिया। अगले मोड़ पर मौजूद दो पुलिसकर्मियों ने समझाया कि यह रास्ता तो कचहरी को जाता है न कि डीसी कार्यालय को।

जुलूस वापस आया तो वहां मौजूद पुलिस से काफ़ी देर तक झक-झक करने के बाद पुलिस वालों को यह समझ में आया कि यह जुलूस नामांकन करने आ रहे संजय मौर्या का है। पुलिस वाले ने अपनी सफ़ाई देते हुए कहा कि उसने समझा था कि ये कोई प्रदर्शनकारी होंगे। उस थानेदार ने बिना यह जाने-समझे ही जुलूस को आगे वालों ने और आगे की ओर धकेल दिया। यदि वह जुलूस वालों की बात सुनता व समझता तो यह सब न होता। इतना ही नहीं, इस नाके से निकल कर जब संजय मौर्या सहित 6 लोग कार्यालय परिसर के गेट पर पहुंचे तो वे बंद थे तथा वहां कुर्सियों पर पसरे पड़े पुलिसकर्मियों ने बिना कुछ सुने-समझे मौर्य सहित 6 लोगों को वापस खदेड़ने का प्रयास किया। काफ़ी देर समझाने के बाद उन्हें समझ में आया कि नामांकन फ़ार्म भरने के लिये उम्मीदवार को यहीं से जाना है तो कहीं जाकर उन्होंने गेट खोला।

अपनी समझ का स्तर दर्शाते हुए पुलिस वालों ने बताया कि उन्हें प्रशासन की ओर से सम्भावित उम्मीदवारों की गाड़ियों के नम्बर दिये गये हैं जिनको बेरोक-टोक प्रवेश करने दिया जाता है। यानी कि बिना गाड़ी वाले उम्मीदवारों को तो प्रशासन एवं पुलिस उम्मीदवार ही नहीं समझती।

जैसे-तैसे चुनाव अधिकारी (डीसी) द्वारा निर्देशित कमरा नं. 108 में घुसने लगे तो चपरासी ने बताया कि पिछले दरवाजे से घुसें। वहां पहुंचे तो बताया गया कि पहले कमरा नं. 102 में जाकर फ़ार्म की जांच करायें। वहां पहुंचे तो वहां भी अफ़रा-तफ़री का माहौल था। स्टाफ़ की पूरी व्यवस्था तक नहीं थी। इसके लिये 2 मेजें और मंगाई गयी। सारी व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास करते पूर्व एडीसी जितेंद्र दहिया ने बताया कि आज पहला दिन है, इसलिये कुछ दिक्कतें आ रही हैं। कल से सब कुछ ठीक ढंग से व्यवस्थित हो जायेगा।

जिस तरह से डीसी कार्यालय सहित समूचे लघु सचिवालय को सुरक्षा के नाम पर घेर कर बंद कर रखा है और कर्मचारी चुनाव के नामांकन जैसे छोटे से काम में उलझे नज़र आ रहे थे, जनता के तमाम काम बंद रहे। यह स्थिति नामांकन के अन्तिम दिन यानी 23 अप्रैल तक बने रहने की सम्भावना है। देश की सरकारी मशीनरी इस कदर लचर हो चुकी है कि एक वक्त में एक ही काम कर सकती है।